सं.ए-45011/2/2019-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

नई दिल्ली, दिनांक: 25th मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञापन

मुझे आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित फरवरी, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

(के. राजारामन)
अपर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23093230/5012

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
5. प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. मन्त्रिमंडल सचिव के निजी सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
   सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, वित्त राज्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी।
10. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
11. अपर सचिव (श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
12. अपर सचिव (एफबी एंड एडीबी), आर्थिक कार्य विभाग।
13. डा. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।
14. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
15. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
    संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (सीएंडसी/यूएनएंडओएमआई)/संयुक्त सचिव (आईपीएफ)/संयुक्त सचिव (एफएम)/सलाहकार (आईईआर)/ संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त)/सीएएए।
16. सुश्री राजश्री रे, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
17. डा. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल), आर्थिक कार्य विभाग।
18. श्री अरूण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
19. श्री आर.सी. गुप्ता, विशेष कार्याधिकारी (एफएटीएफ), आर्थिक कार्य विभाग।
20. मुख्य आर्थिक सलाहकार के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।
21. गार्ड फाइल - 2019

सं. ए.-45011/2/2019-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

विषयः फरवरी, 2019 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।

1. वृहत-आर्थिक सिंहावलोकन

1.1 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2019 को जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, सतत और वर्तमान बाजार मूल्यों पर *सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की बढ़त दरें* वर्ष 2018-19 में क्रमशः 7.0% और 11.5% अनुमानित हैं। वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए सतत मूल्यों पर जीडीपी की बढ़त दरें क्रमशः 8.0%, 8.2% और 7.2% थीं। सीएसओ ने दिनांक 31 जनवरी को अपने पुनरीक्षण में 2016-17 और 2017-18 के जीडीपी में ऊर्ध्वगामी संशोधन किया था। परिणामतः, मूल प्रभाव ने वर्ष 2018-19 हेतु जीडीपी बढ़त को प्रभावित किया है। मौद्रिक दृष्टि में, वर्ष 2018-19 हेतु दूसरे अग्रिम अनुमानों में अनुमानित जीडीपी पहले अग्रिम अनुमानों में अनुमानित जीडीपी से वास्तविक और मामूली दोनों ही मुद्राओं में उच्चतर रही।

1.2 *सतत आधार कीमतों पर सकल मूल्यवर्धित (जीवीए)* वृद्धि दर वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः 8.0%, 7.9% और 6.9% की तुलना में वर्ष 2018-19 में 6.8% अनुमानित रही।

1.3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नई श्रृंखला-संयुक्त) पर आधारित *हैडलाइन मुद्रास्फीति* जनवरी, 2018 में 5.1% की तुलना में जनवरी, 2019 में 2.0% थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति जनवरी, 2018 में 3.0% की तुलना में जनवरी, 2019 में 2.8% थी।

1.4 *10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल* दिनांक 16 फरवरी, 2018 के 7.56% की तुलना में 15 फरवरी, 2019 को 7.58% रहा।

1.5 भारत का *व्यापार घाटा* 2017-18 की पहली छमाही में 74.4 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 1.8 प्रतिशत) से बढ़कर 2018-19 की पहली छमाही में 95.8 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 2.7 प्रतिशत) हो गया। मुख्य रूप से कुल सेवा अर्जनों और निजी अंतरण प्राप्तियों में बढ़त के कारण 2018-19 की पहली छमाही में *निवल अदृश्य प्राप्तियां* उच्च रहीं। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में *निवल एफडीआई अंतर्वाह* 2017-18 की पहली छमाही में 19.6 बिलियन अमरीकी डालर से 17.7 बिलियन अमरीकी डालर तक रह गया। पोर्टफोलियो निवेश में एक वर्ष पूर्व 14.5 बिलियन अमरीकी डालर के अंतर्वाह की तुलना में 2018-19 की पहली छमाही में 9.8 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में 13.2 बिलियन अमरीकी डालर(बीओपी आधार पर) की कमी आई।

1.6 भारत का *विदेशी मुद्रा भंडार* मार्च, 2018 के अंत के 424.5 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 26.2 बिलियन अमरीकी डालर गिरकर 15 फरवरी, 2019 की स्थिति अनुसार 398.3 बिलियन अमरीकी डालर रह गया।

1.7 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (वर्ष 2011-12 की नई श्रृंखला पर आधारित) द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, *औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)* में दिसम्बर, 2017 में 7.3% की बढ़त की तुलना में दिसम्बर, 2018 में 2.4% की बढ़त दर्ज हुई है।

1.8 अप्रैल-नवम्बर, 2017-18 के दौरान 3.7% की बढ़त की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2018-19 की अवधि में संचयी आधार पर औद्योगिक बढ़त 4.6% थी।

1.9 *आठ मुख्य उद्योगों* में जनवरी, 2018 में 6.2 प्रतिशत की तुलना में जनवरी, 2019 में 1.8 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। मुख्य उद्योगों की बढ़त अप्रैल से जनवरी, 2017-18 के दौरान 4.1 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल से जनवरी, 2018-19 के दौरान 4.5 प्रतिशत रही।

1.10 भारत का व्यापारिक माल निर्यात जनवरी, 2018 के दौरान 3.7% की बढ़त दर्शाते हुए 25.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में जनवरी, 2019 में 26.4 बिलियन अमरीकी डालर रहा। भारत का आयात जनवरी, 2018 के दौरान 41.09 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य रहा जो जनवरी, 2018 में 41.08 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात स्तरों से मामूली 0.01% बढ़ा है।

1.11 भारत का तेल आयात जनवरी, 2019 के दौरान 11.2 बिलियन अमरीकी डालर रहा जो कि जनवरी, 2018 में 11.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 3.4 प्रतिशत कम था। व्यापार घाटा जनवरी, 2018 के दौरान 15.7 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे की तुलना में जनवरी, 2019 में 14.7 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था। दिसम्बर, 2018 के दौरान सेवाओं का निर्यात और आयात 17.9 बिलियन अमरीकी डालर और 11.4 बिलियन अमरीकी डालर रहा। सेवाओं में व्यापार शेष दिसम्बर, 2018 में 6.5 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1 (क) वित्तीय प्रतिभूति लेनदेनों पर स्टाम्प शुल्क पद्धति में सुधारों के संबंध में केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणा के अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 में संशोधनों को संसद में वित्त विधेयक, 2019 के भाग के रूप में पुनःस्थापित किया गया। संसद के दोनों सदनों, लोक सभा और राज्य सभा, द्वारा क्रमशः 12 और 13 फरवरी, 2019 को वित्त विधेयक, 2019 पारित कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 21 फरवरी, 2019 को इन संशोधनों को अपनी सहमति दे दी।

(ख) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के माध्यम से भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में सभी वित्तीय सेवाओं का विनियमन करने के लिए

एक यूनिफाइड प्राधिकरण स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया है। यह विधेयक 12 फरवरी, 2019 को राज्य सभा में पेश कर दिया गया है।

(ग) आर्थिक कार्य विभाग ने यूरोपीय पुनर्संरचना एवं विकास बैंक (ईबीआरडी) के साथ भारतीय निजी क्षेत्रों की सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 26.02.2019 को ईबीआरडी के साथ एक कार्यशाला आयोजित की।

(घ) भारत सरकार ने भारत और जापान के बीच अधिकतम 75 बिलियन अमरीकी डालर की राशि तक *द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था (बीएसए)* हेतु एक करार किया है। इस करार पर जापान बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10.01.2019 को बीएसए का अनुमोदन किया गया था। भारत भुगतान शेष का एक पर्याप्त स्तर या लघु-अवधि नकदी का समुचित स्तर बनाए रखने के उद्देश्य से 75 बिलियन अमरीकी डालर की तय राशि का उपयोग कर सकता है। भारत द्वारा बीएसए के एक भाग का विवेकानुसार उपयोग किया जा सकता है। इस समय भारत में विदेशी मुद्रा का स्तर अच्छा है। इस वित्तीय सहयोग से भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी।

(ङ) आर्थिक कार्य विभाग ने सिएर्रा लियोन की सरकार को हाइड्रॉलिक, जल प्रबंधन प्रणाली (सिंचाई) और ट्रैक्टरों की व्यवस्था सहित भूमि और अवसंरचना विकास हेतु एक्जिम बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि की ऋण श्रृंखला के विस्तार का अनुमोदन किया।

(च) "शिमला जल आपूर्ति और सीवरेज सेवा डिलीवरी सुधार कार्यक्रम" के लिए 40 मिलियन अमरीकी डॉलर की विकास पॉलिसी लोन I हेतु (डीपीएल-I) विश्व बैंक के साथ दिनांक 15 फरवरी, 2019 को कानूनी करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

(छ) दिनांक 19 से 20 फरवरी, 2019 के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के भारत के हालिया दौरे के दौरान सऊदी अरब सल्तनत की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि में निवेश करने संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर दिनांक 20/02/2019 को हस्ताक्षर किए गए।

(ज) दिनांक 15 फरवरी, 2019 को रोम, इटली में 20 मिलियन अमरीकी डालर का रियायती भागीदारी लोन (सीपीएल) उपलब्ध कराने हेतु करार पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) के साथ हस्ताक्षर किए गए।

2.2 फरवरी, 2019 के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गईः-

(i) सचिव (आर्थिक कार्य) ने दिनांक 14-15 फरवरी, 2019 को इटली में हुए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) की शासी परिषद के 42वें सत्र में भाग लिया।

(ii) 26 फरवरी, 2019 को पेरिस में जापानी प्रेसिडेन्सी के तहत पहली जी-20 अंतरराष्ट्रीय वित्त वास्तुकला (आईएफए) कार्यदल बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत की ओर से अपर सचिव (एफबी और

एडीबी) ने प्रतिनिधित्व किया, जिसके तहत आईएमएफ के कोटा की 15वीं सामान्य समीक्षा के निष्कर्षों के लिए, जी-20 के प्रख्यात व्यक्तियों वाले समूह की रिपोर्ट और विकास हेतु एलआईसी वित्तीयन संबंधी प्रस्तावों और संभव समाधानों पर विचार-विमर्श किया गया।

(iii) आर्थिक कार्य विभाग की संचालन समिति की 92वीं बैठक दिनांक 14 फरवरी, 2019 को हुई जिसमें विदेशी सहायता से संबंधित 14 परियोजनाओं पर विचार किया गया।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन

विशेषकर, सूचना के प्रस्तुतीकरण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. एसीसी के निदेशों/आदेशों का पालन न किया जाना

शून्य।

5. माह के दौरान स्वीकृत किए गए एफडीआई प्रस्ताव और विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति

स्वीकृत किए गए	:	00
विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित	:	10

***